भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3222

08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

रक्षा पायलट परियोजनाओं में देरी

3222. श्री मणिक्कम टैगोर बी:

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

श्री सुरेश कुमार शेतकर:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विलंबित रक्षा पायलट परियोजनाओं की संख्या और ऐसे विलंब के कारण कुल लागत में वृद्धि;

(ख) रक्षा पायलट परियोजनाओं का विवरण जो पर्याप्त व्यय के बावजूद अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विलंब के लिए किसी की पहचान/जवाबदेही तय की है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई स्वतंत्र लेखापरीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि रक्षा क्षेत्र में कई पायलट परियोजनाओं को पर्याप्त रणनीतिक औचित्य के बिना स्वीकृत किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गैर-उत्पादक/गैर-प्राथमिक रक्षा परियोजनाओं पर सार्वजनिक धन की अधिक बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इन विलंबित रक्षा परियोजनाओं में कोई विदेशी/निजी ठेकेदार शामिल थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार को महत्वपूर्ण रक्षा पायलट परियोजनाओं में विलंब के संबंध में सशस्त्र बलों से कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) डीआरडीओ पायलट परियोजना की श्रेणी के अंतर्गत कोई परियोजना संचालित नहीं करता है। डीआरडीओ भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए मिशन मोड (MM) परियोजनाओं का संचालन करता है।

(ख) से (छ) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****